सार समाचार

ट्रंप ने पूर्व सैन्य मामलों के मंत्री को हटाया

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह वेटरन अफेयर्स सेक्रेटरी (पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री) डेविड शुलकिन को हटाकर इस पद के लिए रॉनी जैक्सन को चुनेंगे। जैक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति के चिकित्सक हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बुधवार को ट्विटर के जरिए 'शुलकिन को देश और पूर्व सैनिकों की सेवा करने के लिए शुक्रिया अदा किया' और कहा कि जैक्सन की इस पद पर पुष्टि होने तक रक्षा के क्षेत्र में कार्मिक व तत्परता सचिव राबर्ट विल्की कार्यवाहक मंत्री का पदभार संभालेंगे। पिछले साल इस पद के लिए शुलकिन को सीनेट ने सर्वसम्मति से चुना था। साथ ही उन्हें दोनों दलों और राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त था। ट्रंप ने वीए में उनकी विधायी जीत की दलील पेश की थी।लेकिन हाल के महीनों में हालात उस वक्त खराब होने शुरू हो गए, जब शुलकिन ने संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा नियुक्त राजनीतिक व्यक्ति नीतिगत मतभेदों के कारण उन्हें हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

इन और उन की मुलाकात 27 अप्रैल को

सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन साल 2007 के बाद पहली बार 27 अप्रैल को मिलेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद गुरुवार को दोनों देशों ने इसकी घोषणा की। समाचार एजेंसी योनहाप ने आधिकारिक संयुक्त बयान के हवाले से कहा कि दोनों नेता पनमुनजोम के सीमावर्ती गांव के दक्षिणी हिस्से में स्थित पीस हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को तीसरे अंतर-कोरियाई शिखर सम्मेलन के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले प्योंगयांग में 2000 और 2007 में इस तरह की मुलाकात हुई थी। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में विचार साझा किए गए, जो हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने को दर्शाता है।उत्तर कोरिया के मुख्य प्रतिनिधि री सोन-ग्वोन ने बैठक की शुरुआत में कहा, पिछले 80 दिनों में कुछ ऐसी नाटकीय घटनाएं हुई हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई। उत्तर कोरिया परमाणु मुद्दे के समाधान पर चर्चा के लिए अप्रैल शिखर सम्मेलन एक मुख्य स्थल की भूमिका निभा सकता है।

विद्यार्थी दलालों के चंगुल से रहें दूर

अमेरिकी दूतावास ने शैक्षणिक वीसा प्रक्रिया आरंभ होने के पहले छात्र-छात्राओं को आगाह किया।

नई दिल्ली ■ वार्ता

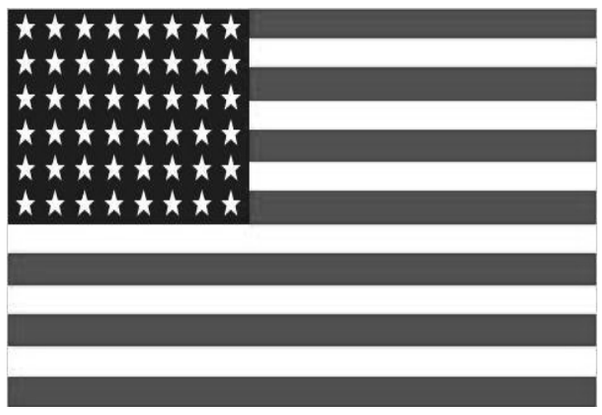

अमेरिकी शैक्षणिक वीसा प्रक्रिया आरंभ होने के पहले अमेरिकी दूतावास ने प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को आगाह किया कि वे किसी भी एजेंट या कंपनी के बहकावे में नहीं आयें और दूतावास की परामर्श सेवाओं का फायदा लेकर सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।

अमेरिकी दूतावास के फेसबुक पेज पर भी विद्यार्थियों को सहायता लेने की सलाह दी गयी है।

अमेरिकी दूतावास के महावाणिज्य दूत जॉर्ज एच होगमैन एवं धोखाधड़ी रोकथाम प्रबंधक एलिज़ाबेथ लॉरेंस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर काउंसलिंग आदि के लिए अमेरिकी दूतावास ने कहीं कोई एजेंट या एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है।

श्री होगमैन ने कहा कि भारत एवं अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में शिक्षा एक केन्द्रीय विषय है और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बढ़ाने की सबसे अहम कड़ी है। अमेरिका इस संबंध को और मज़बूत करने का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस समय भारत के एक लाख 86 हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

सुश्री लॉरेंस ने कहा कि अमेरिका में करीब 4600 विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं जिनमें प्रवेश के लिए विदेशी विद्यार्थी आवेदन करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कई बार बाहर के लोग भरमाने की कोशिश करते हैं कि वे वीसा गारंटी से दिला देंगे और उनके फर्जी दस्तावेज दाखिल करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसियां ये दावा करतीं हैं, वे सब पैसे झटकने के लिए ऐसा करतीं हैं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेबसाइट से अमेरिकी विदेश विभाग के पोर्टल से मदद मिल सकती है। वे किसी एजेंट के झांसे में नहीं आएं। एक सवाल के जवाब में सुश्री लॉरेंस ने कहा कि विद्यार्थी वीसा के आवेदकों के द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं वित्तीय स्थिति को लेकर फर्जी दस्तावेज दाखिल किये जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है।

श्री होगमैन ने कहा कि वीसा के साक्षात्कार विद्यार्थियों से वीसा अधिकारियों के सवालों के जवाब बिना किसी लाग लपेट के साफ-साफ देने की अपेक्षा की जाती है। चतुराई भरे उत्तर दरअसल नुकसान करते हैं। मसलन विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रवेश के उद्देश्य और अपने लक्ष्य के बारे में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। साक्षात्कार में कोई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के समय विद्यार्थी का नर्वस होना स्वाभाविक है पर इससे उसको वीसा मिलने की संभावना कहीं से भी कम नहीं होती है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी के वीसा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह आगे भी असंख्य बार आवेदन कर सकता है लेकिन अगर उसने फर्जी दस्तावेज का प्रयोग किया तो न केवल विद्यार्थी वीसा बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के वीसा पर ताउम्र रोक लग सकती है।

एजुकेशन यूएसए की सलाहकार आस्था विर्क सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यूएसए के फेसबुक पेज के माध्यम से या फिर देश के सात स्थानों पर उनके केन्द्रों द्वारा परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायीं जातीं हैं। इसके अलावा देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शिविर भी लगाये जाते हैं।

फेसबुक ने निजता सेटिंग में किए बड़े बदलाव

वाशिंगटन। सोशल मीडिया साइट के उपयोक्ताओं की निजी जानकारियों के दुरूपयोग को लेकर कड़ी आलोचना के बीच ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के इरादे से फेसबुकने नए निजता टूल (प्राइवेसी टूल) और सेटिंगके विकल्प दिए हैं। इनकी मदद से उपयोक्ता यह तय कर सकेगा कि वह फेसबुक के साथ अपनी किन सूचनाओं और जानकारी को साझा करना चाहता है। सोशल नेटवर्किंग साइट तब आलोचनाओं के घेरे में आ गई थी जब यह खुलासा हुआ था कि वर्ष 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से संबंधित एक ब्रिटिश फर्म ने करोड़ों यूजर्स के निजी डेटा का इस्तेमाल किया है। फेसबुक के मुख्य निजता अधिकारी एरिन एगन और डिप्टी जनरल काउंसेलऐश्ले बेरिंगर ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कंपनी यह समझती है कि उसे'' लोगों कोजागरूक बनाने के लिए और प्रयास करने होंगे।'' उन्होंने कहा कि इन बदलावों पर पिछले कुछ समय से काम किया जा रहा है।

विश्व समाचार / कूटनीति

वेनेजुएला की जेल में आग, 68 कैदियों की मौत

आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चला है।

काराकस ■ एजेंसियां/डेस्क

वेनेजुएला के कैराबोबो राज्य की एक जेल में आग लगने से 68 कैदियों की मौत हो गई है। सुत्रों के अनुसार कैदियों ने जेल से भागने के लिए बुधवार को गद्दों में आग लगा दी थी। कैराबोबो राज्य के मुख्य वकील तारेक साब ने इस घटना के कारणों की जांच के लिए जल्द जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मारे गये ज्यादर कैदी हैं लेकिन जेल में बंद अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आयी दो महिलाओं की भी मौत हो गई है। ज्यादार लोगों की मौत झुलस ने से हुई जबकि कुछ लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। राज्य के एक अधिकारी जेसस संतादर ने कहा कि हालात अब नियंत्रण में है। इस घटना से पूरे राज्य में मातम है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चला है। जेल के हालात की निगरानी करने वाली एक संस्था ने बताया कि पुलिस ने एक बंदी को पैर में गोली मारी जिसके तुरंत बाद गद्दों में आग लग गयी और पूरे जेल में फैल गयी। राहत बचाव दल की रिपोर्ट के अनुसार दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।

अल सिसी दुबारा निर्वाचित हुए

काहिरा। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल- सिसी 92 फीसदी मतों के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार करीब 2.3 करोड़ मतदाताओं ने 63 वर्षीय फील्ड मार्शल सिसी के पक्ष में मतदान किया है। उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी अल घाद पार्टी के प्रमुख मुसा मुस्तफा मुसा को करीब तीन प्रतिशत मत मिलने का अनुमान है। मतदान की प्रकिया कल पूरी हुयी थी। उसके बाद मतगणना शुरू हुयी। गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिसी को देश भर में 2,10,88,295 मत मिले। आधिकारिक नतीजे दो अप्रैल को जारी किए जाएंगे।

मलाला छह साल के बाद पाकिस्तान लौटीं

इस्लामाबाद ■ वार्ता

छह वर्ष के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आज अपनी सरजमीं पाकिस्तान वापस लौटी सबसे कम उम्र की नोबल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि वह पिछले पांच वर्ष से पाकिस्तान लोटने के बारे में सपने देखा करती थीं और उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह अपने देश लौट आयी है।

डॉन न्यूज के मुताबिक सुश्री मलाला ने यहां प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के बाद उनके निवास पर भावुक संबोधन में कहा, 'आज मैं बहुत खुश हूं, साढ़े पांच वर्ष बाद मैंने अपने देश की जमीन पर पैर रखे हैं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है क्योंकि मैं स्वदेश लौटी हूं। मैंने एक बार फिर अपने सरजमीं पर पैर रखे हैं और अपने लोगों के बीच आ गयी हूं।'

उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी शिक्षा ब्रिटेन में भी जारी रखी थी लेकिन मैं हमेशा से पाकिस्तान में आजाद घूमना चाहती थी। मैं बच्चों की शिक्षा पर निवेश करना चाहती हूं। पाकिस्तान की महिलाओं को सशक्त होना चाहिए।'

सुश्री मलाला के बाद श्री अब्बासी ने भी वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि उन्हें देश की बेटी के स्वदेश लौटने पर बेहद खुशी है। उन्होंने कहा, 'आप जब देश छोड़कर गयी थीं, तब आप महज 13 वर्ष की एक किशोरी थीं और अब आप देश की सबसे मशहूर हस्ती हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको सम्मान देती है।ह्यह आपका घर है। अब आप एक आम नागरिक नहीं हैं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।'

उन्होंने कहा, 'आपके देश छोड़कर जाने के बाद से हमने एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है जिसमें 6500 सैनिक, 25 हजार पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल के जवान और आम नागरिक शहीद हुए। आतंकवाद का सफाया कर दिया गया है और अब भी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, उसे दरकिनार कर दें। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।'

कारपोरेट/ कंपनियां/ बैंक

सरकार ने गैस कीमत बढ़ायी

सीएनजी, पाइप वाली रसोई गैस होगी महंगी।

नई दिल्ली ■ भाषा

सरकार ने प्राकृतिक गैस कीदर में छह प्रतिशत की वृद्धि की है और इसके साथ यह दो साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। इससे सीएनजी तथा रसोई गैस के भाव ऊंचे होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू फील्ड से उत्पादित अधिकांश प्राकृतिक गैस की कीमत एक अप्रैल से 3.06 डालर प्रति इकाई (प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) होगी।

यह वृद्धि एक अप्रैल से छह महीने के लिये की गयी है। अभी यह2.89 डालर है। अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे गैस अधशिष वाले देशों में औसत दरों के आधार पर प्राकृतिक गैस की कीमत हर छह महीने बाद निर्धारित की जाती है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब आधा हिस्सा आयात करता है। आयातित गैस की कीमत घरेलू दर के मुकाबले दोगुने से अधिक होती है। यह लगातार दूसरा मौका है जब गैस के दाम बढ़ाये गये हैं।

इससे अप्रैल- सितंबर 2016 के बाद गैस की दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। उस समय इतनी ही कीमत घरेलू उत्पादकों को दी जाती थी। गैस कीमत में वृद्धि से आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन(ओएनजीसी) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी उत्पादक कंपनियों की आय में बढ़ोतरी होगी।

साथ ही इससे सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस महंगी होगी। इसका कारण इसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इससे यूरिया तथा बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। साथ ही गहरे पानी, उच्च तापमान जैसे कठिन क्षेत्रों में नये फील्डों से उत्पादित गैस की कीमत सीमा अप्रैल- अक्तूबर 2018 के लिये बढ़ाकर 6.78 डालर प्रतिइकाई कर दिया गया है। फिलहाल यह 6.30 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। इस वृद्धि से घरेलू गैस आधारित बिजली उत्पादनकी लागत करीब 3 प्रतिशत बढ़ेगी।

साथ ही इससे सीएनजी तथा पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस की कीमत क्रमशः 50-55 पैसे तथा35-40 पैसे प्रति घन मीटर बढ़ेगी। इससे पहले, अक्तूबर 2017- मार्च 2018 की अवधि के लिये गैस कीमत बढ़ाकर2.89 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया गया था। इससे पहले यह 2.48 डालर प्रति इकाई थी। इस बारे में इक्रा ने कहा, '' यह बढ़ोतरी उम्मीद के अनुरूप है। इससे गैस उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी।''

नहीं रुकेगी आईटी उद्योग की वृद्धि

नई दिल्ली, भाषा। साफ्टवेयर व सेवा कंपनियों के शीर्ष संगठन नासकाम के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने आज कहा कि वीजा पर कड़े नियंत्रण जैसे मुद्दों का भारतीय आईटी क्षेत्र पर कुछ असर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे इस क्षेत्र का खेल बिगड़ जाए। चंद्रशेखर का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि अमेरिका, सिंगापुर व आस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में संरक्षणवाद के बीच भारतीय आईटी कंपनियें को अपने कारोबारी माडल में बदलाव करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर ने पीटीआई भाषा से कहा, निश्चित रूप से इनमें से कुछ कारकों का कुछ असर उद्योग पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों से इस उद्योग की वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में नये केंद्र स्थापित करते हुए वीजा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रही हैं।

बिजनेस सुर्खियां

टोयोटा, सुजुकी भारत में बेचेंगी एक दूसरे के वाहन

तोक्यो/ नई दिल्ली, भाषा। जापान की टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारतीय बाजार के लिए एक दूसरे को बिद्युत और पेट्रोलियम ईंधन, दोनों तरह की ऊर्जा से चलने वाली कुछ हाइब्रिड कारों और अन्य वाहनों की आपूर्ति करने का एक प्रथमिक अनुबंध किया है। इसके तहत सुजुकी कंपनी टोयोटा को अपनी प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार विटारा ब्रेजा की आपूर्ति करेगी जबकि टोयोटा उसे अपनी सेडान कोरोला की आपूर्ति करेगी। दोनों कंपनियों ने आज एक संयुक्त बयान में कहा कि इस समझौता का ब्यौरा बाद में तय किया जाएगा। इनमें बिक्री शुरू करने का समय, वाहनों की संख्या और उनकी विशेषताएं, कीमत आदि का फैसला शामिल होगा। बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत एक दूसरे से प्राप्त वाहनों की आपूर्ति इन कंपनियों की भारतीय इकाइयों टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और मारुति सुजुकी इंडिया के नेटवर्क के जरिये की जाएगी।

आरबीआई ने आईसीआईसीआई पर जुर्माना लगाया

मुम्बई, वार्ता। रिजर्व बैंक ने एचटीएम बांड की बिक्री से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।केंद्रीय बैंक ने आज यह जानकारी दी कि 26 मार्च को जारी आदेश के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) बांड की बिक्री और इसके खुलासे के संबंध में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया।उल्लेखनीय है कि कोई भी बैंक तीन श्रेणियों हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), हेल्ड फोर ट्रेडिंग (एचएफटी) और एवेलेबल फोर सेल (एएफएस) में निवेश करता है। बैंकों को अपने डिपोजिट का कम से कम 20 प्रतिशत एचएमटी में निवेश करना होता है। एचटीएम श्रेणी में किया गये निवेश को परिपक्वता से पहले भुनाया नहीं जा सकता है और इन्हें बीच में बेचा नहीं जा सकता है।

सीआईए के मुताबिक

इस साल 65-70 लाख गांठ रूई निर्यात के आसार

नई दिल्ली ■ आईएएनएस

दुनिया का सबसे बड़ा रूई उत्पादक भारत इस साल पिछले साल से ज्यादा रूई का निर्यात कर सकता है। रूई कारोबारियों के शीर्ष संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआईए) के मुताबिक, चालू रूई उत्पादन व विपणन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) के प्रथम छमाही में देश 53-55 लाख गांठ (170 किलो प्रति गांठ) रूई का निर्यात हो चुका है और अगले दो महीने में निर्यात के लिए तकरीबन 10 लाख गांठ के सौदे हो चुके हैं।

सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गंतरा ने गुरुवार को आईएएनएस से मुंबई से फोन पर बातचीत में कहा कि पिछले साल भारत ने 63 लाख गांठ रूई का निर्यात किया था, मगर इस साल 65-70 लाख गांठ रूई निर्यात होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि इसके साथ पिछले साल के मुकाबले देश का आयात काफी कम रहेगा। पिछले साल जहां आयात 27 लाख गांठ हुआ था, वहां इस साल महज 20 लाख गांठ रहेगा। गंतरा ने कहा कि इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल चीन की आयात मांग रूई में बढ़ सकती है, क्योंकि अगले साल उसके पास स्टॉक कम होगा। चीन में इस समय सरकारी भंडार से रूई की नीलामी चल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अगर चीन रूई खरीदना कम करेगा तो निस्संदेह भारत से ज्यादा खरीदेगा, जो भारत के लिए लाभकारी स्थिति होगी। गंतरा ने कहा कि भारत की रूई दुनिया में सबसे सस्ती है, इसलिए इसकी मांग ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने तक भारत का रूई निर्यात बांग्लादेश को 17 लाख गांठ, पाकिस्तान को 11 लाख गांठ, वियतनाम को 10 लाख गांठ, चीन को सात लाख गांठ, इंडोनेशिया और ताइवान को सात लाख गांठ और अन्य देशों को तीन लाख गांठ हो चुका है। सीएआई के पिछले अनुमान के मुताबिक, भारत का रूई उत्पादन इस साल 362 लाख गांठ (170 किलो प्रति गांठ) है, जबकि पिछले साल देश में रूई का उत्पादन 337 लाख गांठ हुआ था। सीएआई ने इस साल घरेलू मिलों की खपत 330 लाख गांठ आंकी है।

निवेशकों की संपत्ति 20.70 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, भाषा। घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत भरोसे के चलते वित्त वर्ष 2017-18 में निवेशकों की संपत्ति 20.70 लाख करोड़ रुपये बढ़ी। इस दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स11 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 2017-18 के दौरान 3,348.18 अंक या 11.30 प्रतिशत मजबूत होकर 32,968.68 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स29 जनवरी2018 को उच्चतम स्तर 36,443.98 अंक तक पहुंच गया था। शेयरों में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 20,70,472 करोड़ रुपये बढ़कर 1,42,24,997 करोड़ रुपये पहुंच गया। रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स के उपाध्यक्ष संदीप चोडिया ने कहा, '' शेयर बाजार के लिये वित्त वर्ष 2017-18 काफी अच्छा साल रहा है।

FIVE CORE EXIM LIMITED

CIN: L32200TN1994PLC026958
Regd. Office: City Centre Plaza, 3rd Floor, Room No. 7/48, Anna Salai, Chennai- 600002, Tel: (91) - 7042292838,
Email: manager.roc@5core.in, Website: www.fivecoreexim.com

NOTICE

This Notice is published **Pursuant to the provisions of section 124 (6)** of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 which have come into force from September 7, 2016.

The Rules interalia, contain provisions for transfer of all the shares in the name of Investor Education and Protection Fund in respect of which dividends have not been paid or claimed by shareholders for seven consecutive years or more.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not paid or claimed for the past 7 years from financial year 2009 – 10, have to be transferred to Demat Account of the IEPF as per IEPF Rules.

In compliance with said Rules, the Company has sent individual notices at the latest available addresses of the Shareholders whose shares are liable to be transferred to the DEMAT account of the IEPF Authority.

The Company has uploaded the full details of such Shareholders and shares due for transfer to the IEPF on its website -http://www.fivecoreexim.com. Shareholders are requested to refer the link to verify the details of unencashed dividend and the shares that are liable to be transferred to the IEPF.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

The concerned Shareholders, holding shares in Physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, Please note that Company would be issuing duplicate share certificates for the purpose of transfer to the IEPF Suspense Account as per the Rules and upon issue of such duplicate share certificates, the original shares certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.

In case no valid claim in respect of equity shares are received from the Shareholders by June 30, 2018, the Company shall with a view to complying with the requirement set out in the rules, transfer the shares to the IEPF as per the procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF.

In case any query the concerned Shareholder may Contact the Company at the Corporate office address of the Company-15B/1, Room No. 203-204, Uggarsain Market, Ashok Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018 or Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Finance & Computer Services (P) Ltd. At Beetal House, 3rd Floor,99, Madangir, behind Local Shopping Centre, near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062,Tel. no. 011 29961281, e-mail beetalrta@gmail.com.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Mrs. Surinder Kaur Kalra
Managing Director

Date: 27.03.2018
Place: Chennai

इस्तेमालशुदा वस्तुओं के आयात की अनुमति

नई दिल्ली, भाषा। सरकार ने इस्तेमालशुदा वस्तुओं के आयात की अनुमति दे दी है ताकि उनकी मरम्मत, नवीकरण आदि किया जा सके। सरकार ने यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय(डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस तरह के सामान की मरम्मत या नवीकरण के दौरान उत्पादित कचरे का निपटान घरेलू नियम कानूनों के तहत किया जाएगा। साथ ही आयातित वस्तुओं का पुनः निर्यात किया जाएगा। एक अन्य अधिसूचना में निदेशालय ने कहा है कि सील मछली का आयात किसी भी रूप में करना प्रतिबंधित है।

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम शुरू

नई दिल्ली, भाषा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना परिचालन आज शुरू कर दिया। इसकी योजना2019 तक500 से अधिक शाखाएं एवं बैंक सुविधाकेंद्र शुरू करने तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने की है। बैंक ने कहा किअभी 18 राज्यों में19 शाखाएं शुरू की जाएंगी। बैंक को इस साल जून तक200 शाखाओं तक पहुंच जाएगा। इन में25 प्रतिशत शाखाएं बैंकों की पहुंच से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। उसने कहा कि उसका जोर वित्तीय समावेश पर रहेगा। जन ग्रुप के चेयरमैन रमेश रामनाथन ने कहा, '' वित्तीय समावेश जन ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। ''

उर्वरक डीलरों का कमीशन 174 रुपये टन बढा

नई दिल्ली, वार्ता। सरकार ने रासायनिक उर्वरक यूरिया की बिक्री करने वाले डीलर या वितरक का कमीशन प्रति टन 180 रुपये से बढाकर 354 रुपये निर्धारित किया है ।नयी दर इस वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगा ।पॉस मशीन से यूरिया की बिक्री करने वाले डीलर को ही कमीशन का भुगतान किया जायेगा ।वर्तमान में निजी एजेंसियों और सहकारिता क्षेत्र को खुदरा दुकानों के माध्यम से यूरिया की बिक्री के लिए प्रति टन 180 रुपये डीलर कमीशन तथा संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से बिक्री के लिए प्रति टन 200 रुपये कमीशन का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के बाद से ही उर्वरक कम्पनियां और और डीलर इस योजना को लागू करनें को लेकर कमीशन बढाने की मांग कर रहे थे सरकारी आकड़ों के अनुसार देश में करीब 23000 डीलर और वितरक हैं जो कमीशन बढाये जाने से लाभान्वित होंगे ।इससे सरकार पर अतिरिक्त सब्सिडी का 515.16 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा ।